P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-12* March- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में श्रमबल का लुइसियन रूपान्तरण एक विश्लेषण

प्रशान्त
शोध छात्र,
गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान,
झूसी, प्रयागराज, भारत

सारांश

भारत में 2004–05 एवं 2011–12 के बीच 3 करोड़ 67 लाख लोगों ने कृषिगत कार्यों से अपने को अलग किया। कृषि में आये इन व्यवसायिक परिवर्तनों को संतोष मेहरोत्रा (2014) ने बताया है कि भारत की आजादी के बाद रोजगार की दृष्टि से आने वाला यह सबसे बड़ा परिवर्तन था। ठीक ऐसा ही आकलन जयाति केसरी (2015) ने अपने आलेख में कहा है, 2004–05 एवं 2011–12 के बीच बड़ी संख्या में कृषिगत कार्यों को छोड़ने वाले लोग निर्माण, विनिमार्ण या सेवाओं के क्षेत्रों में गये हैं।कृषि से गैर कृषि क्षेत्रों की ओर पलायन की व्याख्या लुइसियन रूपांतरण के रूप में की जा रही है। लुइसियन रूपांतरण से अभिप्राय एक ऐसे संरचनात्मक परिवर्तन से है जिसमें कृषि से गैर कृषि की ओर श्रमिकों की स्थानान्तरण होता है। जिसमें रोजगार के अवसरों उत्पादकता तथा पूंजी स्टाक में बृद्धि होती है और नये साधनों के प्रयोग एवं तकनीकि में सुधार होते है नई वस्तुएं, नई प्रकियायें अथवा कच्चे माल के प्रयोग के नये तरीके भी निकलते है लुइसियन रूपांतरण को विश्लेषित करने में 2004–05 66वें एवं 2011–12 68वें दौर के सर्वेक्षणों को ही लिया गया है। इन सर्वेक्षणों की समयावधि भी काफी कम है या इन निष्कर्षों में एक बड़े समय अंतराल को ध्यान में नहीं रखा गया है जो कि लुइसियन रूपांतरण को देखने के लिए अपनाया जाना चाहिए कि इसके लिए हमने नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गेनाइजेशन (एनएसएसओ) के1993–94 50वें और 2011–12 68वें दौर के रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति की यूनिट रिकार्ड डाटा का प्रयोग किया है।

मुख्य शब्द : लुइसियन रूपांतरण, सामान्य मुख्य स्तर (पीएस), गौण स्थिति (एस एस)।

प्रस्तावना

1980 के पूर्व के दशकों में जब भारतीय अर्थव्यवस्था को हिन्दू ग्रोथ रेट के नाम से जाना जाता था। उस समय इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन आया जब भारत हिन्दू ग्रोथ रेट से आगे निकला एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन 2000–2012 के बीच आया जब भारतीय अर्थव्यवस्था को उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन इस उच्च संवृद्धि के समय रोजगार के दशा दिशा में कई उतार–चढाव वाली परिस्थितियां सामने आयीं। रोजगार की स्थिति के बारे में रोजगार वृद्धि दर, बेरोजगारी वृद्धि एवं वेतन वृद्धि जैसे संकेतकों से रोजगार की स्थिति में किसी महत्पूर्ण निष्कर्ष पर नही पहुंचा जा सकता। लेकिन किसी भी विकसित होती अर्थव्यवस्था में रोजगार की स्थिति का सही आंकलन अर्थव्यवस्था में हाने वाले लुइसियन रूपांतरण से जाना जा सकता है क्योंकि लुइसियन रूपांतरण अर्थव्यवस्था में रोजगार की संरचना में सकारात्मक परिवर्तन लाता है।

साहित्यावलोकन

2004–05 एवं 2011–12 के बीच 3 करोड़ 67 लाख लोगों ने कृषिगत कार्यों से अपने को अलग किया। कृषि में आये इन व्यवसायिक परिवर्तनों को संतोष मेहरोत्रा (2014) ने बताया है कि भारत की आजादी के बाद रोजगार की दृष्टि से आने वाला यह सबसे बड़ा परिवर्तन था। "यह रोजगार के क्षेत्र में आने वाला ठीक वही प्रगतिशील परिवर्तन है जो प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन की संरचना में होने वाले परिवर्तनों के हिसाब से होना चाहिए। ठीक ऐसा ही आकलन जयाति केसरी (2015) ने अपने आलेख में कहा है,2004–05 एवं 2011–12 के बीच बड़ी संख्या में कृषिगत कार्यों को छोड़ने वाले लोग निर्माण, विनिमार्ण या सेवाओं के क्षेत्रों में गये हैं। कृषि से गैर कृषि क्षेत्रों की ओर पलायन की व्याख्या लुइसियन रूपांतरण (आर्थर लुईस 1954) के रूप में की जा रही है। बिन्सेंगर (2011) ने अपने लेख में 1960 से 2011 के बीच भारतीय कृषि, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में आये संरचनात्मक परिवर्तनों को

विश्लेषित करते हुए कहते हैं कि 1980 का दशक भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि के विकास का स्वर्णिम दौर था जिसमें कृषि की संवृद्धि दर 3.3 प्रतिशत कृषि श्रमिकों की उत्पादकता 2.3 प्रतिशत तथा कुल साधन उत्पादकता 2 प्रतिशत थी। इन तीनों की (कृषि की संवृद्धि दर 3.3 प्रतिशत, कृषि श्रमिकों की उत्पादकता एवं कृषि में कुल साधन उत्पादकता) के उच्च होने के कारण ही उस दौर में भारतीय कृषि में हरित क्रांति का प्रसार हुआ लेकिन ये कारण आने वाले दशकों में अपने को बनाये नही रख पाये। दो दशकों 1991–2000 एवं 2001–09 कृषि की संवृद्धि दर 2.7 उवं 2.8 प्रतिशत कृषि श्रमिकों की उत्पादकता इन दो दशकों में 1.2 उवं 1.1 प्रतिशत रही एवं कृषि में कुल साधन उत्पादकता 1.5 एवं 1.9 प्रतिशत रही। लेकिन मानसून एवं अन्य संस्थागत कारणों से भारत में कृषि में उतार चढाव बना रहा। विनिर्माण का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान सीमित रहा, शहरी अर्थव्यवस्था में कृषि से बाहर हुए श्रमिकों को रोजगार देने की क्षमता बहुत उल्लेखनीय नही रही। शहर केन्द्रित विकास की नीतियों के बावजूद भी ग्रामीण से शहरों की तरफ जितना पलायन प्रवास एवं विकसित होती अर्थव्यवस्था में होना चाहिए था उतनी तीव्रगति से नही हुआ। गैर कृषि क्षेत्र में एवं कृषि क्षेत्र के श्रमिकों के बीच उत्पादकता में अंतराल परिवर्तन या रूपांतरण कृषि कमजोर धीमा एवं असमान रहा। अपने इसी परिवर्तन में बिन्सेंगर भारत और चीन के 1960–2010 के बीच 1980 के दशक से लेकर तीन दशकों तक कृषि में कुल साधन उत्पादकता 3 प्रतिशत से अधिक बनी रही जो विश्व में सबसे अधिक है। इस कारण से चीन में संरचनात्मक परिवर्तन के स्पष्ट संकेत मिल रहे है वही भारत में कृषि विकास दर में अनियमितता कुल साधन उत्पादकता में उतार चढाव ही भारत में संरचनात्मक परिवर्तनों को कम उत्पादक क्षेत्रों से अधिक उत्पादक क्षेत्रों की ओर श्रमिकों को विश्लेसित किया जाता है। अधिक उत्पादक क्षेत्रों में श्रमिकों का प्रवाह उसी अनुपात मे निर्धारित होगा और यही मांग एवं पूर्ति की गति संरचनात्मक परिवर्तन की गति को भी निर्धारित करेगी।

कुणाल सेन (2016) अपने लेख में कुछ एशियाई देशों चीन, ताइवान, भारत, कोरिया आदि का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और संरचनात्मक परिवर्तनों को निर्धारित करने वाले कुछ कारकों को उल्लेखित करते हैं। भारत में 1994–2012 के बीच एक अच्छी खासी विकास दर देखने को मिली लेकिन इस दौरान कृषि में कार्यबल में मात्र 14 प्रतिशत बिंदुओं की गिरावट आयी जो कि एक दौर के अनुसार काफी कम है जो भारत में संचरनात्मक परिवर्तनों की धीमी एवं असामान्य गति को दर्शाता है। कृषि भारत में विनिर्माण क्षेत्र की प्रकृति का द्वैत किस्म का होना है जिसमें संगठित क्षेत्र की फर्मों की संख्या कम होने के बावजूद उसमें कार्यरत श्रमिकों को सुरक्षा युक्त सुविधाओं तक पहुचा है। लेकिन साथ ही साथ असंगठित क्षेत्र में जिसमे बडी संख्या में फर्में मौजूद है उसमें कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार की सुरक्षा तथा अन्य लाभों तक पहुंच सीमित है संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की उत्पादकता में बढता अंतराल भी है।

जॉसन यंग 2010 तुलनात्मक रूप से भारत और चीन में लुइसियन रूपांतरण को विश्लेषित करते है। और कहते हैं कि भारत एवं चीन पिछले कुछ दशकों से भारत एवं चीन कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से शहरी औद्योगीकृत, सेवा क्षेत्र की ओर बढने का प्रयास कर रहे है। और इस प्रयास में दोनों देशों को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इस प्रक्रिया में चीन को जहां विनिर्माण उद्योग का वैश्विक केन्द्र बनने में सहायता मिली भारत सेवाओं में बडे केन्द्र के रूप में उभरा। इस विकास प्रक्रिया के दौरान भारत एवं चीन ने सकल घरेलू उत्पाद को बढाया शिक्षा एवं स्वास्थ्य और अधोसंरचना को विकसित किया एवं उत्पादन के पैमाने को बढाया। विकास का केन्द्र अगर विनिर्माण एवं सेवाये हैं तो शहरीकरण को बढावा मिलता है। यंग लुइसियन रूपांतरण की प्रक्रिया को शहरीकरण एवं जनसंख्या के वितरण में स्थायी परिवर्तन से जोडकर विश्लेषित करते है। इस प्रक्रिया में शहरी क्षेत्रों में बढते रोजगार के अवसरों के कारण कम उत्पादकता एवं जीवन निर्वाह क्षेत्रों से श्रमिकों का रूपांतरण आधुनिक एवं उच्च उत्पादकता वाले शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कृषि क्षेत्रों में श्रमिकों की अधिकता शहरी क्षेत्रों उद्योगों में अवशोषित नही हो जाती है। लेकिन द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र विकसित नही हैं तो श्रमिकों की एक बडी संख्या को बेरोजगारी का सामना करना पडता है। यूनाइटेड नेशन के आंकडों का प्रयोग करते हुए यंग ने यह दिखाया कि 1981 से 2007 के बीच चीन में भारत की तुलना में शहरों में अधिक जनसंख्या बढी। ग्रामीण क्षेत्र में जहां चीन की जनसंख्या में गिरावट आयी वहीं दूसरी ओर भारत में ग्रामीण जनसंख्या 1980 से 2007 के बीच बढी। 1981 से 1991 तक भारत एवं चीन में शहरीकरण की गति समान थी लेकिन 1991 से 2007 के बीच चीन में शहरीकरण काफी तेजी से बढा। चीन में 2005 में ग्रामीण जनसंख्या की दर नकारात्मक हो गयी। कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात चीन में भारत की तुलना में काफी तेजी से गिरा इसी दौरान उद्योगों में मूल्यवर्धन की प्रक्रिया चीन में भारत की तुलना में अधिक रही। रोजगार की दृष्टि से कृषि में चीन की तुलना में भारत में अधिक लोग कार्यरत है। उद्योगों में चीन में अधिक लोग काम करते है। सेवा क्षेत्रों में भारत में अधिक विकास होने के बावजूद भी रोजगार में सेवाओं में चीन में अधिक लोग कार्यरत है। इसी समय काल में क्रयशक्ति समता एवं प्रति व्यक्ति आय में चीन भारत से काफी आगे निकल गया। लुइसियन रूपांतरण की प्रक्रिया चीन में जहां तीव्र है वहीं भारत में मंद है। भारत इस धीमे लुइसियन रूपांतरण की वजह यंग जनसंख्या नीति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बढती जनसंख्या एवं धीमे शहरीकरण को मानते हैं रूपांतरण की इस प्रक्रिया को अमल में लाने के लिए भारत में कोई सरकारी संस्था नही है लेकिन चीन में है।

अध्ययन का उद्देश्य

अधिकाँश लेखकों ने सामान्य एवं गौड़ (पीएस एस.एस.) को मिला कर एवं सम्पूर्ण देश को एक इकाई मान कर भारतीय अर्थव्यवस्था को रोजगार की संरचना

को लुइसियन रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया हैं। लेकिन ये निष्कर्ष सम्पूर्ण भारत के कार्यबल में शामिल लोगों के आधार पर निकाले जा रहे है। लुइसियन रूपांतरण को विश्लेषित करने में 2004–05 एवं 2011–12 के दौर के सर्वेक्षणों को ही लिया गया है। इन सर्वेक्षणों की समयावधि भी काफी कम है या इन निष्कर्षों में एक बड़े समय अंतराल को ध्यान में नहीं रखा गया है जो कि लुइसियन रूपांतरण को देखने के लिए अपनाया जाना चाहिए। यदि लुइसियन रूपांतरण अगर हो रहा है तो आंशिकया पूर्ण रूप से सत्य है।

1 सामान्य स्थिति (पीस) के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं राज्यों में 1993–94 एवं 2011–12 के बीच आये परिवर्तनों को देखना।
2 सामान्य स्थिति एवं गौड़ स्थिति को साथ लेकर 1993–94 एवं 2011–12 के बीच कृषिगत कार्यों में शामिल कार्यबल का विश्लेषण करना।
3 असंगठित क्षेत्र से श्रमिकों का संगठित क्षेत्र की ओर रोजगार की तलाश में गतिशीलता हो। असंगठित क्षेत्र में प्रति श्रमिक उत्पादकता कम से कम स्थिर हो।

शोध प्रविधि

इस लेख में नेशनल सैंपल सर्वे के 50वें एव 68वे राउंड के डाटा का प्रयोग किया गया है जिसको स्टैटिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस (एसपीएसएस) पर विश्लेषित किया गया ह ैइस विश्लेषण में प्रतिशत परिवर्तन, वार्षिक चक्रवृद्धि दर का प्रयोग किया गया है।

इस लेख का उद्देश्य 50वें दौर 1993–94) से 68वें दौर (2011–12) के मध्य कार्यबल में शामिल लोगों की सामान्य स्तर (पीएस) में कृषि, विनिर्माण, निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यबल में भागीदारी में आये परिवर्तनों का आकलन करना है, जैसा अर्थशास्त्रियों एवं विशेषज्ञों लुइसियन रूपांतरण की बात कही गयी है। उसका पुनः आकलन इस लेखका उद्देश्य है। स्मरण रहे कि संतोष मेहरोत्रा ने (पीएसएसएस) के आधार पर लुइसियन रूपांतरण की व्याख्या की थी। पर इस लेख में सिर्फ (पीएस) के आधार पर यह आकलन किया जा रहा है, क्योंकि पी.एस. में लोग 180 दिनों से अधिक कार्य करते हैं। इसलिए मेरी मान्यता है कि परिवर्तन अधिक स्थायी तब माना जाये, जब पीएस में स्थायी एवं सार्थक बदलाव हो। इस लेख में गौण (एसएस) स्थिति के साथ (पीएसएसएस) का सम्यक आकलन किया जाएगा।

भाग 1

50वें दौर (1993–94) से 68वें दौर (2011–12) में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कार्यबल की संख्या, उसमें परिवर्तन, प्रतिशत बढ़ोत्तरी घटोत्तरी एवं वार्षिक चक्रवृद्धि दर को दर्शाया गया है। यह आकलन एनएसएसओ के प्रतिदर्श पद्धति पर ही आधारित है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कार्यबल का वितरण भी दिखाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि कृषि क्षेत्र में कार्यबल, दो कालखंडो में, 63 प्रतिशत से घटकर 47 प्रतिशत रह गया। खनन एवं उत्खनन, बिजली पानी एवं गैस आपूर्ति में रोजगार का भाग एक प्रतिशत से कम बना हुआ है। बाकी सभी क्षेत्रों में वृद्धि हुयी है, जो सेवाओं में कृषि के बाद सर्वाधिक है सारिणी(1.1)। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि कुल कार्यबल में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है, वहां कृषि क्षेत्र में 0.1 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है। सबसे अधिक संख्या वृद्धि 460 लाख सेवाओं के क्षेत्र में एवं सबसे अधिक प्रतिशत बढ़ोत्तरी 312 प्रतिशत निर्माण के क्षेत्र में दर्ज की गयी

सारणी (1.1) सामान्य स्तर पीएस के आधार पर 50वें दौर (1993–94) एवं 68वें दौर (2011–12) में आल इण्डिया स्तर पर कार्यबल में क्षेत्रवार परिवर्तन(ग्रामीण नगरीय महिला पुरुष)

कुल	50वां दौर		68वां दौर		बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी		CAGR
	लाख में	प्रतिशत	लाख में	प्रतिशत	लाख में	प्रतिशत	
कृषि	1816	62.6	1814	47.0	-2.3	-0.1	0.0
खनन एवं उत्खनन	23	0.8	22	0.6	-0.3	-1.5	-0.1
विनिर्माण	313	10.8	485	12.6	172.7	55.3	2.5
बिजली, पानी एवं गैस आपूर्ति	12	0.4	21	0.6	9.5	79.7	3.3
निर्माण	100	3.4	413	10.7	313.0	312.7	8.2
सेवाएं	640	22.0	1100	28.5	460.4	72.0	3.1
कुल	2903	100.0	3856	100.0	953.0	32.8	1.6

नोट– सीएजीआरः वार्षिक चक्रवृद्धि दर

स्रोत– संकलित यूनिट रिकार्ड डाटा

ग्रामीण भारत की रोजगार संरचना में कृषि का विशेष महत्व है। 50वें दौर में जहाँ कृषि में 1188 लाख पुरुष कार्यरत थे, जिनका रोजगार की संरचना में 74 प्रतिशत भाग था, वहीं 68वें दौर में ग्रामीण पुरुषों की संख्या 1252 लाख हो गयी लेकिन इनका प्रतिशत 64 रह गया सारिणी(1.2)। ग्रामीण पुरुषों की संख्या में कृषिगत कार्यों में बढ़ोत्तरी हुयी लेकिन कृषि का रोजगार की संरचना में प्रतिशत के रूप में कमी आई। कृषि के बाद ग्रामीण पुरुषों के लिए सबसे अधिक बढ़ोत्तरी 225 लाख कामगारों की, निर्माण के कार्यों में रही एवं निर्माण के कार्यों में 433 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी। निर्माण के कार्यों में 9 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर्ज की गयी। ग्रामीण पुरुषों के लिए कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र सेवाओं का रहा, जिसमें 68वें दौर में 396 लाख लोग कार्यरत थे। कुल कामगारों की संख्या में 31 प्रतिशत का परिवर्तन आया।

सारणी (1.2) सामान्य स्तर पीएस के आधार पर 50वें दौर 1993–94) एवं 68वें दौर (2011–12) में ग्रामीण पुरुषों के लिए कार्यबल में क्षेत्रवार परिवर्तन

ग्रामीण (पुरुष)–	50वां दौर		68वां दौर		बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी		CAGR
	लाख में	प्रतिशत	लाख में	प्रतिशत	लाख में	प्रतिशत	
कृषि	1189	73.7	1253	59.2	64	5.4	0.3
खनन एवं उत्खनन	12	0.7	12	0.6	0	-3.2	-0.2
विनिर्माण	114	7.1	174	8.2	60	52.5	2.4
बिजली, पानी एवं गैस आपूर्ति	5	0.3	7	0.3	2	35.5	1.7
निर्माण	52	3.2	277	13.1	225	432.9	9.7
सेवाएं	242	15.0	396	18.7	155	64.0	2.8
कुल	1613	100	2118	100	505	31.3	1.5

स्रोतः संकलित युनिट रिकार्ड डाटा

ग्रामीण महिलाओं के लिए 50वें एवं 68वें दौर में 65 लाख महिलाओं ने कृषिगत कार्यों से अपने को अलग किया। ग्रामीण महिलाओं में कृषि की तरह ही खनन एवं उत्खनन में गिरावट दर्ज की गयी। निर्माणगत कार्यों में ग्रामीण महिलाओं के लिए सर्वाधिक प्रतिशत (429) परिवर्तन देखा गया सारिणी(1.3)। कृषि के बाद सेवाओं में 69 लाख महिलाएं कार्यबल में शामिल थीं। 50वें एवं 68वें दौर में ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यबल में मात्र 0.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी।

सारणी (1.3)सामान्य स्तर पीएस के आधार पर 50वें दौर 1993–94) एवं 68वें दौर (2011–12) में ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यबल में क्षेत्रवार परिवर्तन

ग्रामीण (महिला)–	50वां दौर		68वां दौर		बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी		CAGR
	लाख में	प्रतिशत	लाख में	प्रतिशत	लाख में	प्रतिशत	
कृषि	561	84.8	496	74.5	-65	-11.6	-0.7
खनन एवं उत्खनन	3	0.5	3	0.4	-1	-20.7	-1.3
विनिर्माण	49	7.5	64	9.5	14	28.7	1.4
बिजली, पानी एवं गैस आपूर्ति	0	0.0	1	0.1	0	127.7	4.7
निर्माण	6	1.0	34	5.1	27	428.7	9.7
सेवाएं	41	6.3	69	10.4	28	68.0	2.9
कुल	661	100	666	100	5	0.7	0.0

स्रोतः संकलित युनिट रिकार्ड डाटा

ग्रामीण पुरुषों एवं महिलाओं के लिए कृषिगत कार्यों की संख्या की दृष्टि से एक स्थिरता दिखाई दे रही है, जबकि प्रतिशत के रूप में 77 प्रतिशत से 63 प्रतिशत तक की गिरावट देखी जा रही है। खनन एवं उत्खनन में भी गिरावट देखी जा रही है। निर्माण में सर्वाधिक 432 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है सारिणी(1.4)। निर्माण के बाद सेवाओं में 182 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। ग्रामीण पुरुषों एवं महिलाओं के लिए कुल 22 प्रतिशत का कार्यबल में परिवर्तन आया ळें

सारणी (1.4) सामान्य स्तर पीएस के आधार पर 50वें दौर 1993–94) एवं 68वें दौर (2011–12) में ग्रामीण पुरुषों एवं महिलाओं के लिए कार्यबल में क्षेत्रवार परिवर्तन

ग्रामीण कुल (पु0+म0)–	50वां दौर		68वां दौर		बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी		CAGR
	लाख में	प्रतिशत	लाख में	प्रतिशत	लाख में	प्रतिशत	
कृषि	1749	76.9	1749	62.8	-0.6	0.0	0.0
खनन एवं उत्खनन	15	0.7	14	0.5	-1.0	-6.8	-0.4
विनिर्माण	163	7.2	237	8.5	73.9	45.3	2.1
बिजली, पानी एवं गैस आपूर्ति	5	0.2	7	0.3	2.1	40.3	1.9
निर्माण	58	2.6	311	11.2	252.2	432.5	9.7
सेवाएं	283	12.4	466	16.7	182.8	64.6	2.8
कुल	2274	100	2783	100	509.4	22.4	1.1

स्रोतः संकलित युनिट रिकार्ड डाटा

अगर प्रतिशत परिवर्तन की दृष्टि से देखा जाय तो सबसे अधिक परिवर्तन निर्माण क्षेत्र मे आया है और कृषि मे प्रतिशत परिवर्तन लगभग मामूली है लेकिन गैर कृषि क्षेत्र मे लोगों का आवागमन (खनन एवं उत्खनन को छोडकर) संख्या एवं प्रतिशत दोनों के रूप मे बढोतरी हुई

है अगर संख्या बल को लुइसियन रूपन्तरण का आधार माने जो कि ठीक नही क्योंकि इसमें सिर्फ पुरुषो की संख्या अधिक है महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है लेकिन बहुत ज्यादा नही जिसमे सामान्य स्तर मे कृषि में महिलाओ की भागीदारी ऋणात्मक हैजो कृषि मे एक स्थिर अवस्था को दर्शा रहा है शायद कृषि मे चुनौतियाँ इतनी जटिल न होती तो कृषि को मुख्य रोजगार मानने वाली सामान्य स्थिति संख्या बल एवं प्रतिशत दोनों में बढोतरी दिख रही होती और ये रूपांतरण को चुनौती दे रही है इसी स्थिति को इस स्पष्ट करने के लिए सामान्य एवं गौड़ स्तर को अलग अलग करके अगले खंड में विश्लेषित किया गया है।

भाग–2

उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की रोजगार की संरचना में आ रहे लुइसियन रूपान्तरण को सामान्य स्तर (पीएस+एसएस) अर्थात सामान्य स्थिति (पीस) एवं गौड़ स्थिति (एसएस) को साथ लेकर विश्लेषित करने से सम्बन्धित है। यहां यह बात गौर करने लायक है कि सामान्य स्थिति (पीस) में लोग 180 दिनों से अधिक कार्य करते है एवं गौड स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें लोग साल भर में कम से कम 30 दिनों से अधिक कार्य करते हैं। इस अध्याय में दो गौड़ स्थितियों को लिया गया है एवं वह गौड स्थिति जिसमें लोग सामान्य स्थिति (पीस) के साथ कार्य करते हैं और इसकी गौड स्थिति जिसमें लोग केवल गौड स्थिति में कार्य करते हैं। अध्याय के आगे पन्नों में सामान्य स्थिति (पीएस) एवं दोनों गौड स्थितियों को साथ लेकर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में फिर राज्यों में कृषि में आ रहे परिवर्तनों को विश्लेषित करेंगे।

सामान्य स्तर (पीस) के आधार पर 50वें दौर एवं 68वें दौर में कृषिगत कार्यों में पुरुषों की संख्या में बढ़ोत्तरी देखने को मिली इन दो दौर के बीच अखिल भारतीय स्तर पर 5 प्रतिशत का परिवर्तन आया वहीं पुरुषों के विपरीत महिलाओं में कृषिगत कार्यों की भागीदारी में कमी आयी और इसमें 12 प्रतिशत का ऋणात्मक परिवर्तन आया (सारणी 2.1) अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं एवं पुरुषों को साथ देखने पर कृषिगत कार्यों में 50वें और 68वें दौर के बीच 0.1 प्रतिशत का ऋणात्मक परिवर्तन आया।

सारणी (2.1) सामान्य स्तर पीएस के आधार पर 50वें दौर 1993–94 एवं 68वें दौर में आल इण्डिया स्तर पर कृषिगत कार्यों में कार्यबल में परिवर्तन (सभी)

सामान्य स्थिति (पीएस) कृषि–	50वां दौर (लाख में)	68वां दौर (लाख में)	बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी (लाख में)	परिवर्तन (प्रतिशत)	CAGR
पुरुष	1234	1302	68	5.5	0.3
महिला	582	512	-70	-12.0	-0.7
योग	1816	1814	-2	-0.1	0.0

सभी= (नगरीय ग्रामीण महिला पुरुष)

स्रोतः संकलित युनिट रिकार्ड डाटा

वह गौण स्थिति जिसमें लोग सामान्य स्थिति (पीएस) में भी कार्य करते हैं। (सारणी 2.2) को देखने से यह बात आती है कि इस स्थिति में पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक भागेदारी करते हैं। इस गौड स्थिति में महिलाओं में कृषि छोड़ने का प्रतिशत अधिक (60 प्रतिशत) लेकिन संख्या में पुरुषों (2 करोड़) की तुलना में कम और अखिल भारतीय स्तर पर 3 करोड़ 42 लाख लोगों ने कृषि छोड़ी।

सारणी (2.2) सामान्य स्तर एसएस जिनका सामान्य स्तर पीएस भी है के आधार पर 50वें एवं 68वें दौर के मध्य आल इण्डिया स्तर पर कृषिगत कार्यों में कार्यबल में परिवर्तन (सभी)

सामान्य स्थिति (एसएस) कृषि–	50वां दौर (लाख में)	68वां दौर (लाख में)	बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी (लाख में)	परिवर्तन (प्रतिशत)	CAGR
पुरुष	486	270	-216	-44.4	-3.2
महिला	211	84	-127	-60.1	-5.0
योग	697	354	-343	-49.2	-3.7

स्रोतः संकलित युनिट रिकार्ड डाटा

वह गौड स्थिति जिसमें लोग सिर्फ गौड स्थिति में ही कार्य करते हैं (सारणी 3.3) । उनका कोई सामान्य स्तर (पीएस) नही होता है। इस स्थिति में महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक कार्य करती हैं। इस स्थिति में कृषिगत कार्यों में पुरुषों में (36 प्रतिशत) की गिरावट जबकि महिलाओं की संख्या में अधिक गिरावट दर्ज की गयी। वहीं अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं एवं पुरुषों को साथ लेकर 49 लाख लोगों ने कृषि को छोड़ा है। (सारणी 2.3)

सारणी (2.3) केवल सामान्य स्तर एसएस के आधार पर 50वें एवं 68वें दौर में आल इण्डिया स्तर पर कृषिगत कार्यों में कार्य बल में परिवर्तन (सभी)

सामान्य स्थिति (एसएस) कृषि–	50वां दौर (लाख में)	68वां दौर (लाख में)	बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी (लाख में)	परिवर्तन (प्रतिशत)	CAGR
पुरुष	40	25	-14	-36.5	-2.5
महिला	252	217	-35	-14.1	-0.8
योग	292	242	-50	-17.1	-1.0

स्रोतः संकलित युनिट रिकार्ड डाटा

सामान्य स्थिति और दोनों गौड स्थितियों को मिलाकर अगर विश्लेषण करें तो पुरुषों में 1 करोड़ 62 लाख लोगों ने कृषि छोड़ी एवं महिलाओं में 2 करोड़ 32 लाख महिलाओं ने कृषि छोड़ी। इस प्रकार 50वें दौर एवं 68वें दौर के बीच 3 करोड़ 95 लाख लोगों ने कृषि को छोड़ा है। (सारणी 2.4)

सारणी (2.4) सामान्य स्थिति एवं दोनों गौड स्थिति एसएस के आधार पर 50वें एवं 68वें दौर में आल इण्डिया स्तर पर कृषिगत कार्यों में कार्यबल में परिवर्तन (सभी)

सामान्य स्थिति (पीएस+ एसएस) कृषि–	50वां दौर (लाख में)	68वां दौर (लाख में)	बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी (लाख में)	परिवर्तन (प्रतिशत)	CAGR
पुरुष	1760	1597	-163	-9.2	-0.5
महिला	1046	813	-233	-22.2	-1.4
योग	2805	2410	-395	-14.1	-0.8

स्रोतः संकलित युनिट रिकार्ड डाटा

पीएस और दो गौड एसएस एवं पीएस एवं दोनों गौड एसएस को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था की रोजगार की संरचना में कृषि में आ रहे बदलावों का विश्लेषण किया और पाया गया कि केवल पीएस स्तर पर कृषिगत कार्यों में कमी महिलाओं की कृषिगत कार्यों से खुद को अलग करने से आ रही है। वह गौड स्थिति जिसमें लोग पीएस में भी काम करते हैं उसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा है और केवल गौड स्थिति में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। इन दोनों गौड स्थितियों में पुरुषों एवं महिलाओं की कृषिगत कार्यों की भागीदारी में कमी आ रही है। पीएस एवं दोनों गौड स्थितियों को मिलाकर 50वें एवं 68वें दौर में 3 करोड़ 95 लाख लोगों ने कृषिगत कार्यों से खुद को अलग किया। भारतीय राज्यों में जम्मू कश्मीर एवं उत्तर पूर्व के अधिकतर राज्यों में कृषिगत कार्यों में पीएस एवं दोनों गौड स्थितियों में लोग बढ़े। बाकी सभी भारतीय राज्यों में गिरावट का प्रतिशत कहीं कम तो कहीं अधिक रहा।

निर्माण क्षेत्र मे कार्यरत श्रमिकों की कहानी को जोड़ते है हमें यह समझ मे आता है कि निर्माण में लोगों की भागेदारी इसलिये बढ़ी है क्योंकि इस क्षेत्र में जो कौशल है उसमें बहुत लम्बे प्रशिक्षण की आवश्यकता नही पड़ती है और श्रमिक कार्यस्थल पर ही कार्य करते करते सीख जाते है लेकिन इस रोजगार मे महिलाओ की स्थिति अधिक दयनीय है इनके शोषण , मजदूरी की कम दरे अधिक कठिन कार्य के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ इनको और चुनौतीपूर्ण बनती है।

कृषि और गैर कृषि क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक कार्यबल अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में लगा हुआ है। असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग की एक उप समित ने आकडों के अनुमान के अनुसार जीडीपी में असंगठित क्षेत्र का योगदान 50 प्रतिशत के आस पास है. लगभग 90 प्रतिशत कार्यबल पर कब्जा करने वाले अनौपचारिक श्रमिकों का यह राष्ट्रीय पैटर्न देश के अधिकांश प्रमुख राज्यों के मामले में कमोवेश समान है असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के बीच कृषि क्षेत्र में काफी अनुपात लगभग 65 प्रतिशत भाग लगा हुआ है। जो यह दर्शाने के लिये काफी है कि अनौपचारिक क्षेत्र में कृषि कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्र की प्रधानता है।

देश में अनौपचारिक रोजगार की वृद्धि हमेशा कुल रोजगार की तुलना में कम रही है जो कि अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के तेजी से बढ़ने का कारण है एनएसएसओ के 55 और 66 दौर के आकडों का प्रयोग कर के एनसीईयूएस 2007 बताता है कि देश में वर्तमान में औपचारिक क्षेत्र का अनौपचारिक तेजी से हो रहा है। जहां इसी अवधि में संगठित क्षेत्र में रोजगार की सम्पूर्ण प्रकृति में अनौपचारिकता की प्रवित्ति रही।

भारत में अनौपचारिक क्षेत्र कम उत्पादकता वाले सिंड्रोम से ग्रसित है। इस क्षेत्र की प्रमुख विशेषताओ में निम्न वास्तविक मजदूरी और खराब कामकाजी रहन सहन इत्यादि कई कारण है। इन कारणों को विश्लेषित करने के लिए गृहणियों, सुरक्षा गार्डो , निर्माण श्रमिकों, कपड़ा श्रमिकों, मोची ,बीडी , रेडी वालों, डॉइवर अन्य लोगों के पास बहुत अलग अलग कहानी है। उनकी आय उदारीकरण और सरकार की बदलती नीतियों को अगर मुद्रास्फीति और बढ़ती जरूरतों से मापे तो उनकी वास्तविक आय इसकी पूर्ति करती हुई प्रतीत नहीं होती है।

श्रमिकों की उत्पादकता विभिन्न वर्षों के दौरान

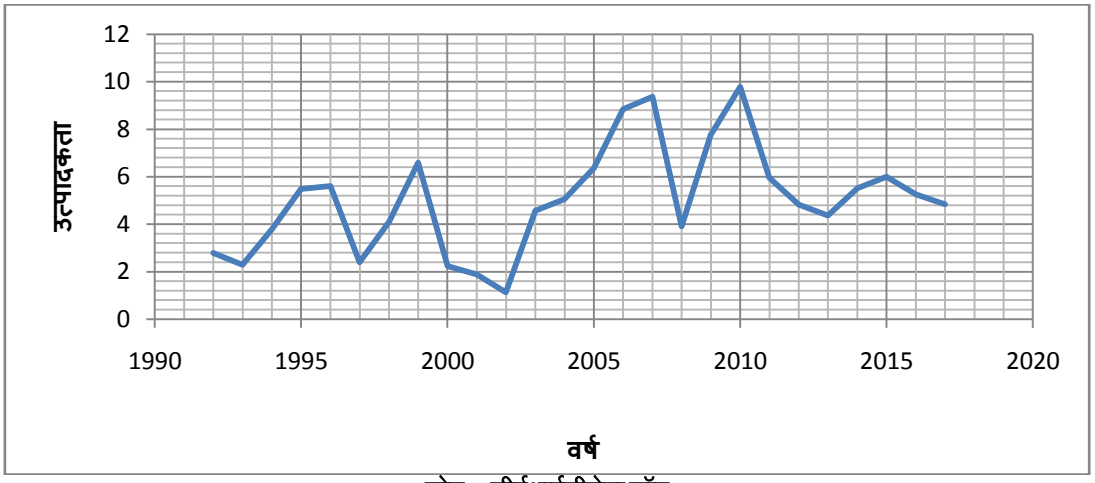

स्रोत : सीईआईसीडेटा.कॉम

ऐसी परिस्थितियों को अगर ध्यान में रखते हुए अगर श्रमिकों की उत्पादकता का आकलन एक बड़े समयकाल में करे तो यह पता चलता है वह स्थिर नही रही है बल्कि उतार–चढ़ाव से भरी रही है। 2007–08 में श्रमिकों की उत्पादकता सर्वाधिक थी जो हाल के दो तीन वर्षों मे नीचे जाने की प्रविति दिखायी दे रही है उत्पादकता को प्रभावित करने वाले संरचनात्मक कारको के अलावा वैश्विक और सरकारी नीतियाँ बहुत व्यापक रूप से प्रभावित करती।

निष्कर्ष

उदारीकरण के बाद से जैसे भारतीय अर्थव्यवथा में वैदेशिक क्षेत्र के लिए खुली उसी समय से रोजगार के अन्य क्षेत्रो में और भी बढ़े लेकिन अर्थशास्त्र मे सीमान्त उत्पादकता का नियम यह कहता है कि कोई भी उत्पादक श्रमिक कों काम तभी देगा जब उसकी उत्पादकता इतनी हो कि उसे प्रति इकाई श्रमिक से लाभ हो लेकिन श्रमिकों की उत्पादकता तभी अधिक हो सकती है जब वहअच्छे ढंग से प्रशिक्षित हो यानि कौशल हो जिससे उसकी उत्पादकता अधिक हो और बढ़ने की ओर अग्रसर हो लेकिन भारतीय समाज में श्रमिकों की उत्पादकता स्थिर नहीं बल्कि उतार चढ़ाव से भरी है। 2007–08 में श्रमिकों की उत्पादकता सर्वाधिक थी जो वर्तमान समय मे नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है लेकिन लुइसियन रूपान्तरण यह कहता है शहरीकरण, उद्योगीकरण के बढने के साथ साथ श्रमिकों को कौशल इत्यादि मिलने से उनकी उत्पादकता बढ़ती है लेकिन एनएसएसओ के विभिन्न सर्वेक्षण बताते है कि श्रम बाजार मे भागीदारी बहुत चुनौतीपूर्ण है और जोखिमों से भरी है जिसके कारण श्रमिकों की स्थिति बेहतर होती है तो वे श्रमबल से बाहर हो जाते क्योंकि उनमें असुरक्षा, छटनी, पारिवारिक समस्यायें इत्यादि होती है। लुइसियन रूपान्तरण की वजह महिलाओ का श्रमबल से बाहर जाना है. अतः इस लेख के अंत में यह कहना होगा उचित होगा कि संख्या बल के रूप में देखें तो श्रमिकों का पलायन भले ही कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र की ओर हुआ हो लेकिन श्रमिको की उत्पादकता एव जीवन की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से इस तरह का लुइसियन रूपांतरण दूर भविष्य के गर्त में है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

बिन्सेंगर मैकेंजी एच.पी. (2012), इण्ड़िया 1960–2010: स्ट्रक्चरल चेंज, द रूरल नान फार्म सेक्टर, एण्ड द प्रास्पेक्ट फॉर एग्रीकल्चर. स्टैनफोर्ड युनिवर्सिटी।

जयाति केसरी पेरिदा (2015), ग्रोथ एण्ड प्रास्पेक्ट ऑफ नॉन फार्म एंप्लायमेंट इन इण्डिया, द जनरल ऑफ इंडस्ट्रियल स्टैटिक, 154–168।

लेविस डब्ल्यू. ए. (1954) इकॉनामिक डेव्लपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर।

एनएसएसओ (1997) एंप्लायमेंट एण्ड अनएंप्लायमेंट इन इण्डिया 50वां दौर. नई दिल्ली : मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एण्ड प्रोगाम इंप्लीमेंटेशन।

एनएसएसओ (2012) एंप्लायमेंट एण्ड अनएंप्लायमेंट इन इण्डिया 68वां दौर. नई दिल्ली : मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एण्ड प्रोगाम इंप्लीमेंटेशन।

संतोष मेहरोत्रा, अंकिता गांगुली, विमल के. साहू (2013) स्टीमेंटिंग द स्किल गैप ऑन रियलिस्टिक बेसिस फॉर 2022 इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पॉवर रिसर्च प्लानिग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया।

संतोष मेहरोत्रा (2014) व्हाई ए जॉब्स टर्न एरांउण्ड डिस्पाइट स्लोइंग ग्रोथ? आईएएमआर।

कुणाल सेन (2016) द डिटरमिनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफारमेंशन इन एशिया : अ रिव्यू ऑफ लिटरेचर एशियन डेव्लपमेंट बैंक इकॉनामिक वर्किंग पेपर सीरीज।

Web Source:ceicdata.com